भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3835

उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2019

फाइबरयुक्त टावर

3835. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में केवल लगभग 25 प्रतिशत टावर ही फाइबर नेटवर्क से जुड़े हैं जबकि विकसित राष्ट्रों में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार, देश में लगभग 31% बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थलों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ लिया गया है। विकसित देशों के संबंध में, कुछ तकनीकी रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि फाइबर से जोड़े गए बीटीएस स्थलों का प्रतिशत अधिक है।

सरकार फाइबर बिछाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से लागत और समय-सीमा का मानकीकरण करने के लिए केन्द्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सम्बंधित नीतियों के अनुरूप एक सहयोगात्मक सांस्थानिक तंत्र के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के मार्गाधिकार(आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दों के समाधान को सुकर बनाती है।

भारतनेट, जो भारत सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से पूर्णतया वित्तपोषित है और विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, के तहत दिनांक 6 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से 1,42,678 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 3,88,838 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में वर्ष 2022 तक कम से कम 60% दूरसंचार टावरों को फाइबर आधारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, मोबाइल संचार उपलब्ध कराने में उपयोग की जाने वाली अवसंरचना और उपकरणों का स्वामित्व विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के पास है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर बीटीएस स्थलों को फाइबर अथवा किसी अन्य साधन से कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है।

*****